



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 1976/अग्राहायण 17, 1898

No. 398] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 1976/AGRAHAYANA 17, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December 1976

G.S.R. 911(E).—The following Order made by the President under sub-section (2) of section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956) is hereby published as required by that sub-section:—

THE HIGH COURT OF RAJASTHAN (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT JAIPUR) ORDER, 1976

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 51 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), the President, after consultation with the Governor of Rajasthan and the Chief Justice of the High Court of Rajasthan, is pleased to make the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the High Court of Rajasthan (Establishment of a Permanent Bench at Jaipur) Order, 1976.

(2) It shall come into force on the 31st day of January, 1977.

2. **Establishment of a Permanent Bench of the Rajasthan High Court at Jaipur.**—There shall be established a permanent Bench of the High Court of Rajasthan at Jaipur, and such Judges of the High Court of Rajasthan, being not less than five in number, as the Chief Justice of that High Court may, from time to time, nominate, shall sit at Jaipur in order to exercise the jurisdiction and power for the time being vested in that High Court in respect of cases arising in the districts of Ajmer, Alwar, Bharatpur, Bundi, Jaipur, Jhalawar, Jhunjhunu, Kotah, Sawai Madhopur, Sikar and Tonk:

Provided that the Chief Justice of that High Court may, in his discretion, order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard at Jodhpur.

New Delhi,
December 8, 1976.

F. A. AHMED,
President.

[No. F.17/2/74-Jus]

P. P. NAYYAR, Addl. Secy.

निम्न, न्याय तथा न्यायिक कार्य संज्ञा

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1976

क्रा०फा०नि० 911(अ).—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश ऐतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जैसा कि उस उपधारा के अधीन अपेक्षित है :—

राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर में स्थाई न्यायपीठ की स्थापना) आदेश, 1976

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 51 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, राजस्थान के राजस्थान तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—

1. सज्जित श्रीरं तथा प्रारम्भ :—(1) यह आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर में स्थाई न्यायपीठ की स्थापना) आदेश, 1976 कहलावेगा।

(2) ये आदेश जनवरी, 1977 के 31वें दिन से लागू होंगे।

2. जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थाई न्यायपीठ की स्थापना :—जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक स्थाई न्यायपीठ स्थापित की जाएगी और राजस्थान उच्च न्यायालय के पांच से अन्धून् ऐसे न्यायाधीश, जिन्हें उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, समय-समय पर नाम निर्दिष्ट करे, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बुन्दी, जयपुर, मुनसु, कोटा, सर्वाई बाघोपुर, बीकानेर तथा टोंक जिलों में उद्भूत होने वाले मामलों के बारे में उस उच्च न्यायालय में तत्समय निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिए जयपुर में बैठेंगे।

परन्तु उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, अपने विवेक से, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी जिले में उद्भूत होने वाला कोई मामला या मामलों का वर्ग जोधपुर में सुना जाएगा।

नई दिल्ली,
8 दिसम्बर, 1976

फखरीन अली अहमद,
राष्ट्रपति।

[सं० फा० 17/2/74-न्याय]

प्रेम प्रसाद नय्यर, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
निर्बन्धक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976